बुनियादी ढांचे के विकास ने बनाया निवेश का कारिडोर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : अपनी दूसरी पारी शुरू करने के साथ ही योगी सरकार ने यह संदेश दे दिया था अर्थव्यवस्था की मजबूती उसकी पहली प्राथमिकता है और एक साल के भीतर ही हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपीजीआइएस-23) ने इसका मजबूत आधार तैयार कर दिया। सरकार के पहले साल को विशेष तौर पर यूपीजीआइएस के लिए जाना जाएगा।

इसके जरिए यूपी को हासिल हुए 33.52 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों ने सरकार के दावों पर बाकायदा मुहर लगाई है। देश के किसी भी राज्य को हासिल होने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव का आंकड़ा है। चुनौती बस इसी बात की है कि निवेश प्रस्तावों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए।

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

योगी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर योगी 2.0 तक नीतिगत सुधारों, कानून व व्यवस्था, प्रगतिशील नीतियों के साथ-साथ लाजिस्टिक सुविधाओं, हवाई अड्डों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, औद्योगिक गलियारों सहित अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड, बुनियादी ढांचे के विकास के आधार पर राज्य में निवेश वातावरण तैयार किया गया। औद्योगिक विकास के लिए विकसित किए गए इको सिस्टम ने यूपी में निवेश का मजबूत कारिडोर तैयार किया है। देश-विदेश में बजे यूपी के डंके की तार्किक वजह भी यही रही और इसी कारण यूपी ग्लोबल समिट में निवेशकों का भरपूर उत्साह भी नजर आया।

रोजगार सृजन का बड़ा जरिया बना एमएसएमई सेक्टर

अर्थव्यवस्था को गति देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है और इसे और बढ़ावा देने के लिए नई एमएसएमई नीति- 2022 घोषित की गई है। इस नीति से रोजगार सृजन में 15% की वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। स्टांप ड्यूटी में छूट सहित तमाम रियायतें दी जा रहीं हैं।

भारत सरकार को भी भाया यूपी का ओडीओपी माडल : उत्तर प्रदेश की एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना का माडल भारत सरकार को भी रास आया है। यही वजह रही कि इस साल केंद्रीय बजट की प्रमुख घोषणाओं में इसे शामिल किया गया। यह सरकार की बड़ी उपलब्धि रही।

इस वजह से निवेशकों की पसंद बन रहा यूपी

- 1225 किलोमीटर के छह एक्सप्रेसवे पूर्ण हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि बीते साल सात अन्य के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए गए। ये विभिन्न चरणों में हैं और पूरे राज्य में मैन्यूफैक्चरिंग केंद्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।
- लखनऊ, वाराणसी एवं कुशीनगर में मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और जेवर तथा अयोध्या में नए हवाई अड्डों के विकसित होने से उत्तर प्रदेश पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है। जेवर में 5,000 हेक्टेयर में भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है।
- वायुमार्ग की घरेलू कनेक्टिविटी के लिए नौ एयरपोर्ट को संचालित करने के बाद पिछले साल 10 और एयरपोर्ट स्थापित करने पर काम किया गया।
- भारत में घोषित दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर में से एक उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत छह नोड्स, अर्थात- आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी एवं चित्रकूट में से अलीगढ़ नोड का उद्घाटन किया जा चुका है। प्रमुख आवंटनों में लखनऊ में ब्रह्मोस तथा झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स शामिल है।
- राज्य सरकार सेमी-कंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग तथा फैब-यूनिट के लिए क्लस्टर विकसित कर रही है। यूपी तेजी से भारत में डाटा सेंटर के मुख्य हब के रूप में उभर रहा है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस शुरू हालांकि गुणवत्ता पर सवाल

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 जुलाई-2022 को जालौन से शुभारंभ किया था। उद्घाटन करने के महज पांच दिन बाद पहली बारिश में एक्सप्रेस-वे की सड़क कई जगह पर धंस गई। बाद में एक्सप्रेस वे को दुरुस्त कर दिया गया लेकिन विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया।

उद्यमियों का मददगार बना

निवेश मित्र : सिंगल विंडो पोर्टलों में से एक 'निवेश मित्र' के माध्यम से राज्य सरकार 29 विभागों की 353 सेवाएं उद्योगों को प्रदान कर रही है। निवेश मित्र पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से भी जोड़ा जा चुका है।

निवेश सारथी : एमओयू की निगरानी के लिए "निवेश सारथी" के नाम से योगी 2.0 में शुरू की गई नई आनलाइन प्रणाली के साथ ही आनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम भी विकसित किया गया है।